इटली के द्वीप सारडिनिया में जगह जगह बड़े- बड़े पत्थरों से बने ढांचे दिखाई पड़ते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में नूरागे और इतालवी में नूरैक्सिस कहते हैं। ऐसे ढांचे सिर्फ यहीं मिलते हैं। ये इमारतें ईसापूर्व 1900 से 730 के बीच नूराजिक सभ्यता द्वारा बनाई गई थीं। माना जाता है कि, पहले यहां 10,000 नूरागे हुआ करते थे, अब 7000 ही बचे हैं। सारडिनिया में वास्तव में 5 प्रकार के नूरागे हैं। पहले हैं, अनियमित आकार प्रकार के प्रोटोनूरागे। ये सबसे ज्यादा प्राचीन हैं। दूसरे हैं, प्रोटोनूरागों का ही विकसित रुप, मिश्रित नूरागे। तीसरे सबसे आम हैं, एकल मीनार नूरागे, जो सारडिनिया में सबसे ज्यादा नज़र आते हैं। शंकु आकार के ये नूरागे "बी हाइव" (मधुमक्खी का छत्ता) जैसे लगते हैं। इसके बाद तानकाडु नूरागे विकसित हुए। इनमें मुख्य टावर के साथ एक गोलाकार भवन भी है। आखिरी हैं, किले जैसे "पॉलीलोब्ड" नूरागे, इन्हें नूराजिक रॉयल पैलेस भी कहते हैं। इनमें टावर्स के साथ कई भवन जुड़े होते थे। शुरुआती यूनानी इतिहासकार मानते थे कि, नूरागे का निर्माण महान शिल्पकार डेडलस ने किया होगा। जिसने क्रीट के पौराणिक दैत्य माइनोटॉर के लिए भूलभुलैया का डिज़ाइन बनाया था। कहा जाता है कि, भूलभुलैया बनाने के बाद वह पहले सिसिली गया और वहां से सारडिनिया चला गया। जहां उसने ये टावर बनाए। पर यह सत्य है या नहीं, यह कौन कह सकता है? तस्वीर में बारुमिनी का सू नुराक्सी नज़र आ रहा है, जो यूनैस्को वर्ल्ड हैरिटेज साइट है। यह नूरागे एक गांव से घिरा हुआ है। ईसापूर्व 1600 से तीसरी सदी इस्वी तक यह गांव आबाद था। साढ़े अठारह मीटर ऊँचे मुख्य नूरागे के चारों ओर एक दीवार है और उस दीवार पर चार मीनारे हैं। बासॉल्ट (ज्वालामुखी का पत्थर) से बना यह समूचा परिसर अपने अनोखे स्थापत्य के लिए विख्यात है। कहा जाता है, कम्बोडिया में जैसे अंगकोर वाट है वैसे सारडिनिया में "सू नूराक्सी" है।

केरल के राज्यपाल ने यू.सी.सी. लागू करने की जमकर वकालत की

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि, यू.सी.सी. लागू करने से मुसलमानों को सबसे बड़ा फायदा होगा, उनके धार्मिक अधिकारों की भी रक्षा होगी

तिरुवनंतपुरम, 13 जुलाई। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गुरुवार को एक बार फिर से समान नागरिक संहिता (यू.सी.सी.) को लेकर अपना समर्थन दोहराया। उन्होंने कहा कि, केवल केंद्र सरकार ही इसे लागू करने काम कर सकती है। राज्यपाल ने कहा, केंद्र को सबसे पहले यू.सी.सी. के उचित कार्यान्वयन के लिए मार्ग प्रशस्त करना होगा। अनुच्छेद 44 कहता है कि समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी है। इस पर भी आपत्तियां उठ सकती हैं लेकिन मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि भले ही अनुच्छेद 44 एक निदेशक सिद्धांत है और सरकार को उचित कार्यान्वयन के लिए एक व्यवस्था के रूप में खड़ा है।" खान ने समान नागरिक संहिता-समय की जरूरत? पर एक सेमिनार को संबोधित करते हुए यह बात कही। केरल के राज्यपाल ने आगे कहा, मेरी राय के अनुसार, हमारे देश में कानून संहिताबद्ध नहीं है बल्कि घोषणात्मक है और विवाह और गोद लेने जैसे विषय धार्मिक कानूनों पर आधारित होने चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने कभी इस बात पर जोर नहीं दिया कि ये धार्मिक कानून क्या होंगे।

- **राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि, यू.सी.सी. का एकमात्र मकसद सभी के लिए एक समान कानून है। खान ने ट्रिपल तलाक जैसे अन्य प्रासंगिक कानूनों का उदाहरण पेश किया और कहा कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिणामस्वरूप 2019 में इसे लागू किए जाने के बाद से मुस्लिम महिलाओं के बीच तलाक की दर में 69 प्रतिशत की गिरावट आई है।**

केरल के राज्यपाल तीन तलाक जैसी प्रथाओं के खात्मे के मुखर समर्थन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने शाह बानो मामले से निपटने के लिए राजीव गांधी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के लिए गुजारा भत्ता के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसे राजीव गांधी की कैबिनेट ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के साथ दरकिनार कर दिया था।

सरकार के कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमजोर कर दिया और मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को तलाक के बाद अपने पूर्व पतियों से गुजारा भत्ता पाने के अधिकार को केवल 90 दिनों तक सीमित कर दिया।

राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि यू.सी.सी. का एकमात्र मकसद सभी के लिए एक समान कानून है। खान ने ट्रिपल तलाक जैसे अन्य प्रासंगिक कानूनों को सामने लाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिणामस्वरूप 2019 में इसे लागू किए जाने के बाद से मुस्लिम महिलाओं के बीच तलाक की दर में 69 की गिरावट आई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इसको अच्छे से लागू किया जाएगा। यू.सी.सी. से मुसलमानों को फायदा होगा।

केरल के राज्यपाल ने आगे कहा, आज की स्थिति इतनी गंभीर है कि, यदि अदालत मेरे पक्ष में आदेश देती है तो मुझे खुशी होगी, लेकिन यदि नहीं तो लोग आरोप लगाते हैं कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। शाह बानो केस की तरह कोई भी आंदोलन खड़ा कर सकता है। ट्रिपल तलाक फैसले में, अदालत ने बताया था कि ट्रिपल तलाक की प्रथा अवैध और असंवैधानिक थी और कुरान में वास्तव में जो कहा गया था उसका भी उल्लंघन था। लोकसभा में यू.सी.सी. 2017 में पारित हो गया था लेकिन राज्यसभा में विपक्षी नेताओं ने इसे बहुमत से पास नहीं होने दिया। विपक्ष के प्रमुख नेताओं ने यू.सी.सी. के कार्यान्वयन का पुरजोर विरोध भी नहीं किया और केवल संसद से वाकआउट किया। जब तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो मुसलमानों को डर था कि उनकी पहचान खत्म हो जाएगी, लेकिन वास्तव में जो हुआ वह मुसलमानों के बीच तलाक की दर में 69 की गिरावट थी। इससे न केवल महिलाओं को बल्कि मुस्लिम बच्चों को भी मदद मिली।

केरल के राज्यपाल ने उन लोगों की भी आलोचना की जिन्होंने दावा किया था कि यदि यू.सी.सी. लागू किया जाता है, तो मुसलमान शादी नहीं कर पाएंगे और अपने शवों को दफन नहीं कर पाएंगे और यह मुसलमानों पर जबरदस्ती थोपा जाने वाला एक हिंदू कानून है। इन आरोपों पर उन्होंने कहा, 1937 का मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, अनुच्छेद 370 के कारण कश्मीर के लिए लागू नहीं था।

70 परिवारों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उपखंड अधिकारी से जवाब मांगा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश स्थानीय निवासियों की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि राज्य सरकार ने 2019 में रूपवास उपखंड में नई ग्राम पंचायत कंजोली बनाई। इस नई ग्राम पंचायत में माडापुरा ग्राम पंचायत के कमालपुरा व श्रीनगर गांव के 70 से भी ज्यादा परिवारों के नाम जोड दिए। जबकि नई ग्राम पंचायत उनसे 8 किमी दूर थी। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और स्थानीय प्रशासन सहित राज्य सरकार को प्रतिवेदन दिया, लेकिन 2020 में ऑनलाइन सिस्टम की वजह से लगभग दर्जनों परिवारों के नाम नई ग्राम पंचायत में डाल दिए गए, जबकि निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने पूर्व में इनको नई ग्राम पंचायत में शामिल नहीं करने के आदेश दिए थे। वहीं उसी के अनुसार साइट मैप भी बनाया था। याचिका में कहा गया कि नई ग्राम पंचायत में नाम शामिल करने से ग्रामीण राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे और निजी जरूरतों के लिए उन्हें 8 किमी दूर जाना होगा। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

फ्रांस में मोदी का भव्य स्वागत, बैठकों का दौर शुरु हुआ

मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस "बैस्टिल डे" परेड के आयोजन में मुख्य अतिथि होंगे

पेरिस, 13 जुलाई (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर गुरूवार दोपहर यहां पहुंच गये और फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया।

मोदी का हवाई अड्डे पर रस्मी स्वागत किया गया तथा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रधानमंत्री शुक्रवार को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे पर होने वाले समारोह तथा परेड में विशिष्ट अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। भारत और फ्रांस इस वर्ष रणनीतिक साझेदारी की 25 वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।

मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले

- **फ्रांस की प्रधानमंत्री ऐलिज़ाबैथ बोर्न ने हवाई अड्डे पर प्र.मंत्री मोदी की अगवानी की तथा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।**

प्रधानमंत्री सुबह फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज यहां फ्रांस की यात्रा पर पहुंचने के बाद मेज़बान देश की प्रधानमंत्री एलिज़ाबेथ बोर्न के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय बैठक करने के साथ ही सीनेट के अध्यक्ष गेरार्ड लार्चर से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार फ्रांस की यात्रा पहुंचने पर पेरिस में सबसे पहले श्री मोदी की फ्रांस की सीनेट के अध्यक्ष गेरार्ड लार्चर के साथ सार्थक बैठक हुई।

उन्होंने आपसी हित के कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और कई क्षेत्रों में भारत-फ्रांस सहयोग को गहरा करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि इस मुलाकात में मोदी ने रेखांकित किया कि कैसे लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के साझा मूल्य, साझीदारी के मूलभूत लोकाचार बनाते हैं। चर्चा में भारत की जी20 प्राथमिकताओं, प्रौद्योगिकी के उपयोग में लोकतांत्रिक मूल्यों, दोनों उच्च सदनों के बीच सहयोग के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई।

सहायक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि उसके खिलाफ दर्ज प्रकरण में एफ.आर. लगाने की एवज में अनुसंधान अधिकारी अमीर चंद 11 हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर परेशान कर रहा है।

जिस पर शिकायत का सत्यापन कर गुरूवार को टीम ने ट्रैप की कार्यवाही करते हुए बसैया गांव के निवासी अमीरचंद को परिवादी से दस हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

पुलिस के द्वारा आरोपी ए.एस.आई. अमीर चंद के भरतपुर की एल.बी. शास्त्री नगर कॉलोनी सेवर स्थित आवास पर भी ए.सी.बी. की टीम के द्वारा तलाशी की कार्यवाही जारी है। उल्लेखनीय है कि आरोपी सहायक उपनिरीक्षक पुलिस द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान भी परिवादी से एक हजार रूपये वसूले थे। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। एसीबी के द्वारा इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

देश में 24.7 लाख से अधिक लोग एड्स पीड़ित

- **यूनाइटेड नेशन्स एड्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2010 के मुकाबले एड्स पीड़ितों की संख्या में 42 प्रतिशत की कमी आई है तथा एड्स की मृत्यु दर में 77 प्रतिशत की गिरावट हुई है।**

नयी दिल्ली, 13 जुलाई (वार्ता) देश में एचआईवी. एड्स से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या 24.7 लाख से अधिक है जबकि वर्ष 2010 के मुकाबले इनमें 42 प्रतिशत की कमी आई है।

संयुक्त राष्ट्र एड्स की बृहस्पतिवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2022 में भारत में एचआईवी से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या अनुमानित 24 लाख 70 हजार रही है। इसी वर्ष एच.आई.वी. से 66,000 नई संक्रमित संक्रमित हुए हैं। हालांकि वर्ष 2010 के मुकाबले वर्ष 2022 तक सर संक्रमित की संख्या में 42 प्रतिशत की कमी आई है। वैश्विक स्तर पर यह औसत 38 प्रतिशत रहा है। भारत में वर्ष 2022 में 38000 व्यक्तियों की मृत्यु का कारण एड्स से संबंधित रहा है। वर्ष 2010 की तुलना में एड्स से मृत्यु दर में 77 प्रतिशत की गिरावट हुई है।

रिपोर्ट में एड्स एचआईवी से निपटने में भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने कोविड-19 के दौरान भी एड्स से निपटने के संसाधनों में कमी नहीं आने दी। सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए वर्ष 2021-25 के लिए 193.4 करोड़ डालर का आवंटन किया गया है।

आई.एम.एफ. ने पाकिस्तान...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बढ़ेगी। पाकिस्तान पहले ही अत्यधिक राजनैतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, इन सुधारों के लागू होने से स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ेगी।

इस समय तो आई.एम.एफ. केवल 1.2 अरब डॉलर ही देगा तथा शेष राशि आर्थिक सुधार पैकेज के लागू हो जाने के बाद ही जारी की जायेगी।

क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जो आई.एम.एफ. की मैनेजिंग डॉयरेक्टर तथा उस कमेटी की अध्यक्ष हैं, जिसने पाकिस्तान के बेल-आउट पैकेट को हर कोण से जाँचा-परखा है, ने कहा कि बुरे समय में दी गई यह सुविधा "पाकिस्तान को एक ऐसा अवसर प्रदान करने वाली है कि वह वृहद इकोनॉमिक स्थिरता प्राप्त कर सके तथा नीतिगत सुधारों की सतत क्रियान्विति के जरिये इन असंतुलनों का समाधान कर सके।" आई.एम.एफ. की नीतिगत हिदायतों का उद्देश्य पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को खोलना तथा सुधारों को लागू करना है ताकि बाजार की ताकतें, वहाँ खुले तौर पर अपना खेल दिखा सकें। उदाहरण के लिये, विदेशी विनिमय रिफॉर्म, संबंधित देश की अर्थव्यवस्था को बाहरी विकास के प्रति समायोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करते हैं। यह सुविधा पाकिस्तान को एक बहुत ही मुश्किल वक्त पर मिली है। गत वर्ष, जब आर्थिक स्थिति बहुत मुश्किल दौर में थी, उस समय आई विनाशकारी बाढ़ तथा देश की गलतियों के परिणामस्वरूप भारी राजकोषीय घाटा सामने आ गया था।

इन सब कारणों के फलस्वरूप देश के भंडारों में कमी आने लगी तथा विदेशी आघात देश को और ज्यादा प्रभावित करने लगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था, जिसमें पहले ही बहुत से अभाव एवं परेशानियाँ मौजूद हों, में आई.एम.एफ. के सुधार एजेंडा को लागू कर पाना कोई आसान काम नहीं है।

आई.एम.एफ. की हिदायतें यह कह रही हैं कि टैक्स बढ़ाने से सरकार की वित्तीय स्थिति में संतुलन की कुछ झलक दिखाई देगी। 2024 के निर्धारित बजट में वर्तमान वर्ष के गैपिंग घाटे की तुलना में कुछ सरप्लस है। टैक्स दरें बढ़ाने वाला कोई भी कदम निस्संदेह रूप से देश में बहुत ज्यादा अलोकप्रिय रहेगा तथा कटु आलोचना का केन्द्र सिद्ध होगा।

वर्ष 1991 में, भारत की ऐसी ही स्थिति थी क्योंकि उससे पहले कुछ साल तक आर्थिक प्रबंधन में ढ़िलाई रही थी। लेकिन, नीतिगत सुधारों की दृढ़निश्चयी कोशिश तथा उसे बाद बाजार की ताकतों के उभरने से अर्थव्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन आये थे तथा सतत ग्रोथ दिखाई दी थी। उसके बाद, भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकेगा।

प्र.मंत्री शहबाज शरीफ अगस्त में प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगे

इस्लामाबाद, 13 जुलाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घोषणा कर दी है कि, वे अगस्त में प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगे। शहबाज शरीफ ने गुरुवार को राष्ट्र के नाम एक संबोधन में कहा कि, मौजूदा सरकार अगस्त में देश की बागडोर कार्यवाहक सरकार को सौंप देगी। पीएम शहबाज ने कल भी ऐसी ही घोषणा की थी। शहबाज शरीफ ने बुधवार को भी कहा था कि, वर्तमान सरकार का कार्यकाल 14 अगस्त को समाप्त हो जायेगा और निर्वाचन आयोग अगले आम चुनाव की तारीख की घोषणा करेगा। 'डॉन' अखबार की खबर के अनुसार सत्तारूढ गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठक के अगले दिन शरीफ की यह टिप्पणी आई है। खबर के मुताबिक बैठक के दौरान पीडीएम प्रमुख

- **प्र.मंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि, वे 14 अगस्त को सत्ता छोड़ देंगे।**

ने समय से एसेम्बली को भंग करने और चुनाव कराने की जरूरत पर जोर दिया।

पाकिस्तान को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 3 अरब डॉलर के कर्ज की मंजूरी मिल गई है। इससे पाकिस्तानी रुपये में मामूली उछाल देखा गया है। निवेशकों के विश्वास की बहाली, पाकिस्तानी रुपये और शेयर बाजार में उछाल व फिच द्वारा पाकिस्तान की रेटिंग में सुधार का जिक्र करते हुए, शहबाज शरीफ ने कहा कि ये सभी "आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढने की झलक" है। उन्होंने कहा, देश के सामने अब केवल एक ही रास्ता है - भीख का कटोरा फेंकना और अपने पैरों पर खड़े होना।" उन्होंने कहा, दूसरों पर निर्भरता की ये बेड़ियां तभी टूट सकती हैं जब हम कड़ी मेहनत में विश्वास करेंगे, अपने वादे पूरे करेंगे और ईमानदारी से देश की सेवा करेंगे। आइए एक राष्ट्र बनें। पाकिस्तान की संसद का पांच साल का कार्यकाल 12 अगस्त, 2018 को तत्कालीन पीटीआई सरकार के तहत शुरू हुआ था और पिछले साल अप्रैल में अविश्वास मत के माध्यम से पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान के निष्कासन के बाद पीएम-शहबाज के नेतृत्व वाले सत्तारूढ गठबंधन के तहत पूरा होगा। अपने संबोधन की शुरुआत में, प्रधानमंत्री ने याद किया कि उन्हें पिछले साल अप्रैल में देश चलाने और "इसके कल्याण के लिए काम करने" की "पवित्र जिम्मेदारी" दी गई थी।

अपने आरोपित नेताओं...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कार्यवाही माना गया था। केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष द्वारा लखीमपुर में किसानों को कुचलकर मार डालने की वीभत्स घटना के बाद की गई मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की माँग अनुसुनी कर दी गई थी। गौतम अडानी की कंपनियों द्वारा स्टॉक में की गई चालबाजी से संबंधित सनसनी खेज हिंडनबर्ग रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद भी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी के वरिष्ठ नेतागण चुप्पी धारण किये रहे। इससे पूर्व 2015 में, भाजपा नेतृत्व उस समय भी अप्रभावित एवं भावशून्य बना रहा था जब विपक्ष ने तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस्तीफे की माँग की थी, क्योंकि यह बात उजागर हो गई थी कि स्वराज ने पूर्व आई.पी.एल. प्रमुख ललित मोदी, जो वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपी थे, को इंग्लैंड जाने के लिये वीज़ा दिलवाने में मदद की थी।

जैसा कि पिछले ट्रैंड बता रहे हैं, आरोपी मंत्रियों या सांसदों के इस्तीफे माँग लेने को चुनावी जीत की सुनिश्चित गारंटी के रूप में नहीं लिया जा सकता। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार के दौरान, कई मंत्रियों एवं नेताओं से इस्तीफे ले लिये गये थे- जिनमें अश्विनी कुमार से लेकर पवन कुमार बंसल, सुरेश कलमाड़ी, ए. राजा कनिमोझी तथा महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण शामिल थे। लेकिन यू.पी.ए. द्वारा प्रदर्शित ये उच्च नैतिक मूल्य 2014 के लोकसभा चुनावों में मतदाताओं का समर्थन हासिल नहीं कर सके थे। हो सकता है कि एम.जे. अकबर की कुर्बानी इसलिये दे दी गई हो क्योंकि वे राजनैतिक रूप से प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन बृजभूषण का उत्तर प्रदेश की करीब चार लोकसभा सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव एवं नियंत्रण है। इसलिये इस मामले में भाजपा नेतृत्व के समक्ष दुविधा का भारी संकट दिखाई दे रहा है।

अब नॉन ए.सी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शयनयान वाली भी बनेगी। इसमें स्वाभाविक रूप से कम किराया लिया जाएगा। रेलवे का इरादा है कि पुराने डिब्बे जोड़ कर बनने वाले रैक वाली गाड़ियों की जगह ट्रेनसेट को लाया जाये।

शयनयान वाली वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने के लिए टिटलागढ़ सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड एवं भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने काम शुरू दिया है। इसकी शुरुआती डिज़ायन बन कर रेल मंत्रालय में स्वीकृति के लिए आयी है। वंदे भारत के स्लीपर कोच की डिज़ायन मौजूदा ट्रेनों के डिज़ायन से एकदम भिन्न है और इसमें अधिक आरामदेह सीटों के साथ साथ कई सुविधाएं भी दी जाएंगी।

मौजूदा कुर्सीयान वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के उन्नयन एवं विविधीकरण की दिशा में एक और अहम कदम उठाते हुए रेलवे ने उसके रंग और डिज़ायन में कुछ बदलाव किये हैं। केसरिया एवं चॉकलेटी रंग की वंदे भारत एक्सप्रेस में शौचालय में लाइटिंग एवं वाश बेसिन में कुछ परिवर्तन किये गये हैं। एग्ज़ीक्यूटिव श्रेणी की सीटों में फुट रेस्ट एवं सीटों के पीछे झुकाने के कोण में बदलाव किया गया है ताकि यात्री अधिक आराम महसूस करे। विद्युत पारेषण के लिए पेंटोग्राफ अधिक ऊंचाई वाले ओएचई के लिए अनुकूल बनाया गया है।

कुएं में पड़ा मिला युवती...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करवा पा रही है। उन्होंने कहा कि दलित युवती जो कि नादौती पढ़ाई करने जाती थी उसे रात को 3 बजे बदमाश मुंह में कपड़ा डालकर ले गए। उन्होंने आशंका जताई है कि युवती के साथ गैंगरेप किया है तथा उसके ऊपर एसिड डाला है, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद युवती को बदमाशों ने कुएं में फेंक दिया है। उन्होंने कहा कि युवती के साथ हुए पूरे घटनाक्रम का खुलासा पोस्टमार्टम के बाद ही होगा। सांसद मीणा ने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पीड़ित परिवार एवं भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाएगी और उसके बाद आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर सांसद डॉक्टर मीणा के साथ एकत्रित हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मा डागुर ने कहा कि बालिका के लापता होने पर परिजन पुलिस थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक अभी तक यहां नहीं आए हैं। उन्होंने मांग की है कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, घटना के आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए तथा युवती के परिवार जनों को 20 रु. लाख की आर्थिक सहायता एवं सरकारी नौकरी प्रदान की जाए।

दिल्ली में यमुना के जलस्तर ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा

बाढ़ की भारी आशंका के चलते दिल्ली सरकार ने सभी स्कूल-कॉलेज और कार्यालयों को रविवार तक बंद करने का आदेश दिया है

नई दिल्ली, 13 जुलाई (वार्ता)। राष्ट्रीय राजधानी में यमुना के बढ़ते जलस्तर 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और गुरुवार अपराह्न एक बजे तक जलस्तर 208.62 मीटर तक पहुंच गया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद यहाँ के सभी स्कूलों-कॉलेजों और विश्विद्यालयों के साथ दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों को रविवार तक के लिए बंद करने का आदेश दिया है।

- **गुरुवार दोपहर एक बजे तक जलस्तर 208.62 मीटर तक पहुंच गया, अगर हिमाचल और उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय इलाकों में भारी बरसात का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो दिल्ली में हालात भयावह हो सकते हैं।**
- **यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से इस समय तीन मीटर ऊपर चल रहा है।**

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में आज डी.डी.एम.ए. की बैठक में यमुना में बढ़ते जल स्तर को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केजरीवाल ने निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि यमुना का जल स्तर अभी बढने की संभावना है इसलिए आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों को रविवार तक बंद करने का आदेश दिया गया है। सभी कर्मचारी रविवार तक घर से ही काम करेंगे। प्राइवेट संस्थानों को भी एडवाइजरी जारी कर अधिक से अधिक वर्क फ्राम होम करने की अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद करना पड़ा है। इससे 25 फीसद पानी का प्रोडक्शन कम हो गया है। दिल्ली सरकार पानी की राशनिंग कर रही है।

केजरीवाल ने कहा कि यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ने की वजह से नदी के आसपास की सड़कों पर पानी आ गया है। उन्होंने कहा कि यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। अब यह सुबह के 208.46 से बढ़कर अपराह्न एक बजे तक 208.62 मीटर पर पहुँच गया है। बढ़ते हुए जल स्तर के कारण, यमुना के आस पास की सड़कों पर आ गया है। आपसे अनुरोध है कि इन रास्तों पर न जायें।

चुनाव क्या ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबको यह कह दिया और हम सब ने उनको यह विश्वास दिला दिया कि हमारे यहां कोई गुट नहीं है। हमारे यहां केवल एक गुट है और वह है राहुल गांधी, खड़गे का कांग्रेस का गुट। इसके अलावा हमारा कोई गुट नहीं है, हम सबकी अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इससे पहले पायलट ने कहा कि चुनाव सिर पर आ गए हैं। कोई कह रहा है चुनाव में 100 दिन हैं, कोई कह रहा है 90 दिन है। मैं तो कहता हूं शून्य दिन हैं।

आप मानिए आज से ही चुनाव चालू हो गए हैं। कब चुनाव अभियान का आगाज़ होगा, दिल्ली से घोषणा होगी, उसका आप इंतजार मत कीजिए। जिन्हें अपनी सीट पर जीत का डंका बजाना है, वे आज से ही फील्ड में जुट जाएं।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 **अजमेर कार्यालय:** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908